



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 469]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 3, 1986/आश्विन 11, 1908

No. 469]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 1986/ASVINA 11, 1908

इस भाग में भिन्न-विभिन्न संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग-अलग संख्या की रूप में

रखा जा सके

Separate Pagings is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

कार्मिक लोक शिपियत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1986

प्रतिपक्षार्थ

सा.का.नि. 1129 (घ)—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 15) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में कर्नाटक सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर 6 अक्टूबर, 1986 से कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण की एतद्वारा स्थापना करती है जो कि इस अधिनियम के खण्ड 3 की धारा (ग) के प्रयोग से "विशेष दिन" होगा।

[सं. ए-11019/20/86-ए.डी.]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 3rd October, 1986

NOTIFICATIONS

G.S.R. 1129(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the

Central Government on receipt of a request in this behalf from the Government of Karnataka, hereby establishes the Karnataka Administrative Tribunal with effect from the 6th day of October, 1986 which shall be the 'appointed day' within the meaning of clause (c) of section 3 of the Act.

[No. A-11019/20/86-AT]

सा.का.नि. 1130 (घ)—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (नियम) नियम, 1986 है।

(2) ये सारकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इस नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) "अधिकर्ता" से किसी पक्षकार द्वारा अपनी ओर से अधिकरण के समक्ष आवेदन या उत्तर प्रस्तुत करने के लिये सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "आवेदक" से धारा 19 के अधीन अधिकरण को आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "आवेदन" से धारा 19 के अधीन अधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(ङ) "प्रपत्र" से इन नियमों के भाष्य संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है।

(च) "सरकार" से कर्नाटक सरकार अभिप्रेत है।

(छ) "विधि व्यवसायी" का वही अर्थ होगा, जो उसका अधिकारिता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) में है;

(ज) "रजिस्ट्रार" से अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकारी भी है जिसको नियम 27 के खण्ड (2) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियाँ और कृत्य प्रत्यायोजित किए जाएँ;

(झ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ञ) "अन्तर्गत आवेदन" से ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही जो धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन अधिकरण को अन्तर्गत की गई है, अभिप्रेत है;

(ट) "अधिकरण" से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित कर्नाटक राज्य प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है;

(ठ) इसमें जिन शब्दों तथा वाक्यांशों का इस्तेमाल तो किया गया है परन्तु उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में किया गया है।

3. अधिकरण की भाषा.—(1) अधिकरण की भाषा अंग्रेजी होगी, परन्तु अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के पक्षकार यदि ऐसा चाहें तो कन्नड़ में तैयार की गई दस्तावेजों भी फाइल कर सकेंगे;

परन्तु यह और कि स्यायपीठ अपने विवेकानुसार कार्यवाहियों में कन्नड़ का प्रयोग अनुज्ञात कर सकेंगे किन्तु अन्तिम आदेश अंग्रेजी में होगा।

4. आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया.—(1) अधिकरण को आवेदन आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकर्ता द्वारा या सम्यक् प्राधिकृत अधिकारिता द्वारा अथवा आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रेषण में प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्री शक द्वारा रजिस्ट्रार को सम्बोधित करने सेवा जाएगा।

(2) उपनियम (i) के अधीन आवेदन फाइल के आकार के एक कोरे लिफाफे के साथ जिस पर प्रत्यर्था का पूरा पता हो, एक अभिलेख पुस्तिका प्ररूप में तीन पूर्ण सेटों में प्रस्तुत किया जाएगा और जहाँ प्रत्यर्था की संख्या एक से अधिक है, वहाँ आवेदक द्वारा फाइल के आकार के अपेक्षित संख्या में कोरे लिफाफे के साथ जिन पर प्रत्येक प्रार्थना का पूरा पता होगा, प्रत्यर्थियों की संख्या के बराबर अभिलेख पुस्तिका प्ररूप में आवेदन पत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँगी।

(3) आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ प्ररूप संख्या 2 में एक रसीद पत्र संलग्न करेगा तथा प्रस्तुत करेगा जिस पर आवेदन पत्र की प्राप्ति की पावती के रूप में रजिस्ट्रार द्वारा अथवा रजिस्ट्रार की ओर से आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे।

(4) उपनियम (1), (2) तथा (3) में दी गई किसी बात के बावजूद भी, अधिकरण निम्नलिखित अनुमति दे सकता है:

(क) एक से अधिक व्यक्ति मिलकर एक संयुक्त आवेदन पत्र वापर कर सकते हैं, जबकि बाध में प्रवेश तथा बाधित राहत के स्वरूप को व्याप्त

में रखकर अधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि सेवा के मामले में उपर्युक्त समान हित है; अथवा

(ख) संयुक्त आवेदन पत्र में शामिल होने के इच्छुक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसिएशन को किन्तु शर्त यह है कि आवेदन पत्र में ऐसे वर्षा व्यक्तियों के नाम तथा बने/बेनी/बेब बिण् माएँ जिनकी ओर से यह दावा किया गया है।

5. आवेदनों का प्रस्तुत किया जाना और उनकी संवीक्षा.—(1) रजिस्ट्रार, या उनके द्वारा नियम 4 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, प्रत्येक आवेदन पर बह तारीख पृष्ठांकित करेगा जिसकी बह उस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई है या प्रस्तुत की गई समझी गई है और उन पृष्ठांक पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) यदि संवीक्षा पर, आवेदन अकार्यवाह पाया जाता है, तो वह सम्यक् रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उसे कम संख्यांक दिया जाएगा।

(3) यदि संवीक्षा पर आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और त्रुटि-गत त्रुटि प्ररूपित प्रकृति की है, तो रजिस्ट्रार अपनी उपस्थिति में उस त्रुटि का परिशोधन करने के लिए पक्षकार को अनुज्ञात कर सकेगा और यदि उस त्रुटि प्ररूपित प्रकृति की नहीं है तो रजिस्ट्रार त्रुटि का परिशोधन करने के लिए आवेदक का ऐसा समक्ष अनुज्ञात कर सकेगा जो वह शीघ्र समझे।

(4) यदि सम्बद्ध आवेदक उपनियम (3) में अनुज्ञात समय के भीतर त्रुटि का परिशोधन करने में असमर्थ रहता है तो रजिस्ट्रार ऐसे कारणों में त्रुटि निवेदन किया जाएगा, आदेश द्वारा आवेदन को रजिस्ट्रार करने से इंकार कर सकेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध धीरे-धीरे ऐसा आदेश करने के 15 दिन के भीतर अधिकरण को की जाएगी जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

6. आवेदन फाइल करने का स्थान.—आवेदन आवेदक द्वारा रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा।

7. आवेदन फीस.—रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ रु. 50 (पचास पचास रुपये) फीस दी जाएगी जो कि आवेदन पत्र पर लगाई गई कोर्ट की स्टैम्प के रूप में की जाएगी;

परन्तु यह कि जहाँ अधिकरण एक से अधिक व्यक्ति अथवा एसोसिएशन द्वारा एक ही आवेदन पत्र वापर किए जाने को अनुमति देता है, वहाँ दण्ड शून्य रु. 50 (पचास पचास रुपये) होगा।

8. आवेदन की अन्वेषण.—(1) नियम 4 के अधीन फाइल किए गए प्रत्येक आवेदन में युक्तिपूर्ण तरीके के अधीन संज्ञित ऐसे आवेदन के आधारों को उपस्थित किया जाएगा और ऐसे आधार कमत्र. संख्यांकित किए जाएँगे और प्रत्येक किस के मोटे कागज के एक तरफ दोहरी पार्श्वों में अंकित किए जाएँगे।

(2) अन्तर्गत आवेदन या निदेश मांगने के लिए पृथक् आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा यदि आवेदन या अन्तिम निवेदन उपस्थित रखकर आवेदन में अन्तर्गत आवेदन या निदेश मांगने का निवेदन किया गया है।

(3) कोई आवेदक अधिनियम की धारा 19 के अधीन आवेदन पत्र वापर करने के बाह अन्तर्गत आवेदन अथवा निदेश के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा आवेदन पत्र यथासंभव उसी प्ररूप में होगा जो धारा 19 के अधीन किसी आवेदन पत्र के लिए निर्धारित है और इसके साथ रुपये 2 (दो रुपए) फीस होगी जो कि ऐसे किसी आवेदन पत्र पर लगाई गई कोर्ट की स्टैम्प के रूप में देय होगी।

9. आवेदन के साथ भेजा जाना वाले दस्तावेज—(1) प्रत्येक आवेदन के साथ एक आवेदन पुस्तिका संलग्न की जाति जिसमें निम्नलिखित होंगे—

- (i) उस आवेदन का प्रस्तावित प्रति निहित प्रमुख आवेदन काव्य किया गया है ;
- (ii) वे सभी दस्तावेज जिन्हें आवेदन द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जिनका आवेदन में उल्लेख किया गया है ; तथा
- (iii) दस्तावेजों का अनुक्रमणिका।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों में किसी विधि द्वारा साक्षी द्वारा जमा या जमापत्र अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा प्रत्येक दस्तावेज को अनुक्रम क्र-1; क्र-2, क्र-3 तथा आगे भी इसी क्रम में क्रमबद्ध रूप में अंकित किया जाएगा।

(3) जहाँ आवेदन पत्र किसी अभिकर्ता द्वारा दायर किया जा रहा हो, वहाँ ऐसे अभिकर्ता का अधिकृत करने वाले दस्तावेजों को भी आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।

परन्तु जहाँ आवेदन पत्र किसी विधि व्यवसायी द्वारा दायर किया गया है या जहाँ साथ सम्बन्ध निम्नलिखित "वकालतनामा" होता।

10. जहाँ डाक-1—प्रत्येक आवेदन के उद्देश्य पर अध्यापित होगा और इनमें एक या एक से अधिक अनुशंगों को लागू कर आगे बढ़ते बखत कि प्राप्ति अनुशंग एक दूसरे के पर्याप्तिक हों।

11. प्रत्यर्थी पर आवेदन का नोटिस तामील करना—(1) अभिलेख पुस्तिका में आवेदन के एक प्रति सामान्य प्रत्येक प्रत्यर्थी पर रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित में से एक क्रम में तामील का जाएगा—

- (i) आवेदक के माध्यम से अथवा बाद तामील करने वाले के माध्यम से दलील;
- (ii) पक्षी महित रजिस्ट्री डाक द्वारा; यद्यपि
- (iii) अगर उल्लिखित किसी भी रीति में संघर्षित विभागकायदा के माध्यम से।

(2) जहाँ अधिकरण द्वारा जारी किया गया नोटिस आवेदक द्वारा स्वयं दलील रूप से तामील किया जाता है, वहाँ वह (आवेदक) तामील किए जाने से सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ, तामील रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा तथा प्रत्येक तामील एक पथोपत तामील मानी जाएगी।

(3) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के बावजूद भी न्यायाधिकरण प्रत्यर्थियों की संख्या तथा उनके विवाय स्थानों तथा अन्य परिस्थितियों का ध्यान में रखकर यह निर्देश दे सकता है कि प्रत्यर्थियों पर आवेदन पत्र का नोटिस प्राविष्टापित तामील की रीति महित किसी अन्य रीति से तामील किया जाएगा जो रजिस्ट्रार को उचित तथा सुविधानुक प्रतीत होगी।

(4) सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय न्याय सरकार प्रथम उनके विभागों की ओर से, मामले के स्वतंत्र तथा प्रत्यावश्यकता का ध्यान में रखते हुए, ऐसे निर्देशों के अधीन जैसा कि अधिकरण उचित समझे, नोटिसों को स्वीकार करेगा।

(5) अधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रत्येक नोटिस के साथ जब तक धन्यथा निर्देश न हो, अभिलेख पुस्तिका के साथ आवेदन पत्र की एक प्रति होगी।

(6) प्रत्येक आवेदक ऐसे किसी आवेदन पत्र के बावजूद प्रत्यर्थियों की संख्या पांच से अधिक हो प्रत्येक तामील तथा निम्नलिखित किए जाने के लिए निम्नलिखित फीस देगा—

- (i) पांच से अधिक प्रत्यर्थी होने पर प्रत्येक प्रत्यर्थी के लिए रु 5/- (पांच रुपए केवल), यद्यपि
- (ii) जबकि तामील ऐसी रीति से किया गया है जैसा कि उपनियम (3) के अधीन रजिस्ट्रार ने निर्देश दिया था तो ऐसी रजि और तामील करने में व्यय होने में व्यय हुई हो और रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की गई हो।

(7) उपनियम (3) अथवा उपनियम (6) के (अधीन प्रत्येक तामील करने अथवा निष्पादित करने के लिए फीस आवेदक द्वारा कोई भी स्टैम्प के रूप में जमा कराई जाएगी।

(8) उपनियम (1), (2), (3), तथा (4) में दी गई किसी बात के होते हुए भी यदि न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आवेदन का नोटिस सभी प्रत्यर्थियों पर तामील करना व्यावहारिक रूप से उचित नहीं है या यह निर्धारित किए जाने वाले कारणों से यह निवेश दे सकता है कि आवेदन पत्र पर मुनवाई इस बात पर ध्यान दिए बिना की जाएगी कि कुछ प्रत्यर्थियों को आवेदन पत्र का नोटिस तामील नहीं किया गया था बखत कि किसी भी आवेदन पत्र पर मुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक कि—

- (i) आवेदन पत्र का नोटिस सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार पर तामील किया गया हो यदि उक्त सरकार एक प्रत्यर्थी है ;
- (ii) आवेदन पत्र का नोटिस उस अधिकारी पर तामील कर दिया गया है जिनके यह आवेदन पत्र किया था जिनके विरुद्ध आवेदन पत्र दायर किया गया है, यद्यपि
- (iii) न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि जिन प्रत्यर्थियों पर आवेदन पत्र का नोटिस तामील नहीं किया गया है उनके हितों का उन प्रत्यर्थियों द्वारा जिन पर आवेदन पत्र का नोटिस तामील किया गया है, रक्षण रूप से प्रतिनिधित्व होता है।

12. प्रत्यर्थी द्वारा उत्तर और अन्य दस्तावेजों का फाटन किया जाना—(1) प्रत्येक प्रत्यर्थी जो आवेदन का प्रतिवाद करना चाहता है उस पर आवेदन का सूचना तामील किए जाने की तारीख के एक मास के भीतर वह रजिस्ट्रार का आवेदन पत्र का उत्तर देने हुए अभिलेख पुस्तिका के प्रथम में तीन पूर्ण सैट फाटन करेगा जिनके साथ में ऐसे दस्तावेज भी होंगे, जिन पर उनके संरोध किया है।

(2) उपनियम (1) के अधीन दायर आवेदन के उत्तर में प्रत्यर्थी, आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में दिए गए तथ्यों को विनिश्चित रूप से स्वीकार करेगा, इंकार करेगा अथवा स्पष्टीकरण देगा तथा मामले पर यथोचित निर्णय लिए जाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अतिरिक्त तथ्यों का भी उल्लेख करेगा। इस पर प्रत्यर्थी द्वारा या सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 15 के अर्ध 6 में वर्णित देश से उनके द्वारा निश्चित रूप में बकायश प्राधिकृत किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और निश्चित बयान के रूप में सत्यापित किया जाएगा।

(3) उपनियम (2) में उल्लिखित दस्तावेज भी उत्तर के साथ दायर किए जाएंगे तथा उन्हें भाग 1, भाग 2, भाग 3 (और आगे इसी प्रकार) अंकित किया जाएगा।

(4) प्रत्यर्थी उपनियम (1) में यथा वर्णित दस्तावेजों के साथ उत्तर की एक प्रति आवेदक पर अथवा विधि व्यवसायी पर, यदि कोई हो, तामील करेगा और ऐसी तामील का प्रमाण रजिस्ट्रार को दायर करेगा।

(5) रजिस्ट्रार प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन जाने पर एक मास की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् उत्तर फाटन करने की अनुज्ञा दे सकता।

13. मुनवाई की तारीख और समय का अधिसूचित किया जाना—रजिस्ट्रार पक्षकारों को अथवा उनके वकीलों को यदि कोई है आवेदन की मुनवाई की तारीख और समय अधिसूचित करेगा।

14. न्यायाधिकरण की बैठक—न्यायाधिकरण की बैठकें सामान्यतः बंगलोर में होंगी।

किन्तु शर्त यह है कि यदि किसी समय अधिकरण का अधिवेशन इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण न्यायाधिकरण की बैठक बंगलोर से भिन्न किसी अन्य स्थान पर करना आवश्यक है तो अध्यक्ष ऐसे किसी उचित स्थान पर बैठक करने का निवेदन दे सकता।

15. आवेदन के पक्षों का निर्णय :—(1) अधिकरण स्थानांतरित किए गए आवेदन पक्षों की सुनवाई के लिए एक कलेंडर तैयार करेगा और यथासंभव मामलों की सुनवाई तथा निर्णय कलेंडर के अनुसार करेगा।

(2) प्रत्येक आवेदन पक्ष की सुनवाई तथा निर्णय यथासंभव इसके प्रस्तुत किए जाने के छः मास के भीतर कर लिया जाएगा।

(3) उपनियम (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए अधिकरण का यह अधिकार है कि वह किसी स्वयं में मना करे और जबानी दलीलों के लिए समय सीमा कर सकेगा।

16. आवेदक के व्यक्तिगत के कारण आवेदन पर कार्यवाई :

(1) जहां आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी अन्य तारीख को जिसको ऐसी सुनवाई स्थिति कर दी जाए, आवेदक उस समय हाजिर नहीं होता है जब आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार होता है, वहां अधिकरण अपने विवेकानुसार, या तो व्यक्तिगत के कारण आवेदन को खारिज कर सकेगा या उसकी सुनवाई करके गुणवत्ता के आधार पर इसका निरीक्षण कर सकेगा।

(2) जहां आवेदन व्यक्तिगत के कारण खारिज कर दिया जाता है और आवेदक तत्पश्चात् हाजिर हो जाता है और अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि उसकी उस समय गैर हाजिरी का पर्याप्त कारण या जब आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार हुई थी, वहां अधिकरण आवेदन को खारिज करने वाले आवेदन को अपास्त करने वाला एक आदेश करेगा और उसे बहाल करेगा।

17. आवेदन पर एक पक्षीय सुनवाई :

(1) जहां आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी अन्य तारीख को जिसको सुनवाई स्थिति कर दी गई है, आवेदक हाजिर होगा है और प्रत्यर्थी उस समय हाजिर नहीं होता है जब आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार हुई हो वहां अधिकरण अपने विवेकानुसार आवेदन को स्थिति या उसकी सुनवाई कर सकेगा और आवेदन का एकपक्षीय रूप से निरीक्षण कर सकेगा।

(2) जहां किसी प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों के विरुद्ध आवेदन पक्ष की सुनवाई एकतरफा हुई हो तो ऐसा/ऐसे प्रत्यर्थी आवेदन को निरस्त करने के लिए अधिकरण से निवेदन कर सकते हैं और यदि ऐसा/ऐसे प्रत्यर्थी अधिकरण की यह संतुष्टि कर दे कि नोटिस विधिवत सामील नहीं किया गया था, अथवा वह/वे आवेदन की सुनवाई के समय पर्याप्त कारण से हाजिर नहीं हो सके थे तो अधिकरण उनके विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई को निरस्त करने हुए एक आदेश ऐसी शर्त पर कर सकेगा जो वह उपरि समझे और आवेदन पर आगे कार्यवाई के लिए कोई अन्य विधि नियत कर देगा।

किन्तु जहाँ यह है कि जहां एकपक्षीय सुनवाई का स्वरूप ऐसा है कि इसे एक प्रत्यर्थी के विरुद्ध निरस्त नहीं किया जा सकता तो ऐसे सभी के विरुद्ध अथवा अन्य किसी भी प्रत्यर्थी के विरुद्ध निरस्त किया जा सकेगा।

और यह कि कोई भी अधिकरण आवेदन की एकपक्षीय सुनवाई मात्र इस कारण से निरस्त नहीं करेगा कि नोटिस सामील किए जाने में अनियमितता हुई थी जबकि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि प्रत्यर्थी को सुनवाई की तारीख के बारे में जानकारी थी और हाजिर होने तथा आवेदक के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था।

18. आवेदन का स्थगन :—अधिकरण ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, और कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर आवेदन की सुनवाई स्थिति कर सकेगा।

19. आवेदन पर हस्ताक्षर किया जाना और उस पर तारीख, आदिमा अधिकरण का प्रत्येक आवेदन लिखित रूप से होगा और उस पर सम्बद्ध व्यापक का गठन करने वाले अवधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और तारीख दर्शाई जाएगी।

20. आवेदों का प्रकाशन : अधिकरण के ऐसे आवेदों को जो किसी अधिकृत रिजिस्ट्रार या प्रेस में प्रकाशन के लिए प्रेषित किए जाएं, ऐसे निबंधनों और पक्षों पर जिन्हें अधिकरण अधिकृत करे, ऐसे प्रकाशन के लिए निर्मुक्त किया जा सकेगा।

21. आवेदों का पक्षकारों को संसूचित किया जाता : (1) आवेदन पर पारित प्रत्येक आदेश आवेदक को और प्रत्यर्थी को या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रार आफ द्वारा निगूळ संसूचित किया जाएगा।

(2) पक्षकारों द्वारा कार्यवाहियों के आवेदन की प्रमाणित प्रतियाँ प्रत्यक्ष द्वारा किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा यथास्थिति शर्तों तथा शर्तों का सुगतान करके रजिस्ट्रार को आवेदन देकर प्राप्त की जा सकती है।

22. आवेदों के निरीक्षण के लिए कोई फीस नहीं :—किसी पक्षित आवेदन के किसी पक्षकार द्वारा उनके प्रतिवेदों के निरीक्षण के लिए कोई फीस प्रसारित नहीं की जाएगी।

23. कुछ मामलों में आवेदन और निवेदन :—अधिकरण ऐसे आवेदन कर सकेगा या ऐसे निवेदन दे सकेगा जो उसके आवेदों को प्रभावी करने के लिए या उनके संबंध में या उसकी आवेदिका के दुरुपयोग के निवारण के लिए या न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

24. विधि व्यवसायी के लिपिक का रजिस्ट्रार :—(1) किसी विधि व्यवसायी द्वारा नियोजित और उस अधिकरण के जिसमें विधि व्यवसायी विधि-व्यवसाय करता है, आवेदों के अभिलेख की पहचान रखने और उनकी प्रतियाँ अभिप्राप्त करने के लिए अज्ञात लिपिक को "रजिस्ट्री कृत लिपिक" के रूप में जाना जाएगा।

(2) वह विधि व्यवसायी जो अपने लिपिक या रजिस्ट्रार कराने का इच्छुक है, लिपिक को पासपोर्ट आकार की तीन फोटों के साथ प्रत्यक्ष 3 में रजिस्ट्रार को एक आवेदन करेगा, तथा इनमें से एक फोटों आवेदन फार्म पर चिपकाई जाएगी तथा दो फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएंगी।

(3) एक विधि व्यवसायी एक समय पर या से अधिक रजिस्ट्रीकृत लिपिक नहीं रखेगा जब तक कि रजिस्ट्रार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा अनुज्ञात न करे।

(4) सभी रजिस्ट्रीकृत लिपिकों का एक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार के कार्यालय में रखा जाएगा और जिनके रजिस्ट्रार के तहत रजिस्ट्रार ऐसे रजिस्ट्रीकृत लिपिक को एक पहचान पत्र जारी किए जाने का निदेश देगा जो अनन्तरणीय होगा और अधिकरण के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य कार्यकारी द्वारा अनुरोध पर वारक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) उपनियम (4) में वर्णित पहचान पत्र अधिकरण के उप-रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा।

(6) जब कभी कोई विधि व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत लिपिक को नियोजित करना इच्छा कर देता है तो पुराने वह उस समय की सूचना उसके लिपिक को जारी किए गए पहचान पत्र के साथ पत्र के माध्यम से रजिस्ट्रार को देगा और ऐसे पत्र का प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत लिपिक का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया जायगा।

(7) लिपिक का रजिस्ट्रेशन एक वर्ष की अवधि के लिए विधिवानुसार होगा तथा इसका नवीनीकरण किया जाएगा।

25. अधिकरण के काम के बारे में निम्नलिखित—(1) अधिकरण के कार्य घंटे वही होंगे जैसे कि सरकार के कार्यालयों के हैं—अधिकरण रविवारों को तथा सरकार द्वारा अपने कार्यालयों के लिए अप्रत्यक्ष नियुक्त कर्मियों को बंद रहेगा।

(2) अध्यक्ष उन दिनों की प्रतिवेदन नाम लिखित प्रत्येक दिवस के दौरान अधिकरण द्वारा 30 दिन का अवकाश एक बार अवकाश उसके अधिक बार मनाया जाएगा।

26. अधिकरण की बैठक के बंदे—अधिकरण (जिसके अध्यक्ष प्रावधान न्यायपीठ भी है) की बैठक के बंदे अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए सामान्यतया 11.00 पूर्वाह्न से 2.00 अपराह्न तक और 3.00 अपराह्न से 5.00 बजे प्राह्न तक होंगे।

27. रजिस्ट्रार की शक्तियाँ और कर्तव्य—(1) रजिस्ट्रार अधिकरण के अभिलेखों की अभिरक्षा रखेगा और ऐसी अन्य कृत्यों का जो उसका नियमों के अधीन अवकाश अवकाश द्वारा भी किया जाता होगा।

(2) रजिस्ट्रार अध्यक्ष के अनुमोदन में उस-रजिस्ट्रार को इन नियमों द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए प्रेषित कृत्यों को प्रत्यापोजित कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रार को अनुमति होगी कि वह किसी भी व्यक्ति को अधिकरण में अध्यक्ष द्वारा लिखित काम में शामिल कोई अन्य अधिकारी रजिस्ट्रार के सभी अथवा किसी भी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(4) अधिकरण की प्रारम्भिक मुद्रा रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(5) रजिस्ट्रार अध्यक्ष द्वारा लिखित आदेशों के विरुद्ध निराला के अधीन रहते हुए, अधिकरण की मुद्रा किसी आदेश, समन या अन्य कार्यवाही पर लगा सकेगा।

(6) अधिकरण की मुद्रा रजिस्ट्रार के लिखित आदेशों के बिना अधिकरण के किसी आदेश की प्रमाणित नहीं होगी।

28. रजिस्ट्रार की अतिरिक्त शक्तियाँ और कर्तव्य—इन नियमों में अन्यत्र प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार की संघटित न्यायपीठ के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त होंगे, अर्थात्—

- (i) सभी आवेदन और अन्य दस्तावेज जिसके अन्तर्गत अप्रतिष्ठित आवेदन भी हैं, प्राप्त करना;
- (ii) आवेदन रजिस्ट्रीकृत किए जाने से पूर्व उनकी संवीक्षा से उद्भूत होने वाले सभी प्रश्नों का निरीक्षण करना;
- (iii) अधिकरण को प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन में अधिविषय तथा नियमानुसार संशोधन कराए जाने की अपेक्षा करना;
- (iv) अधिकरण के निदेशों के अधीन रहते हुए आवेदनों या अन्य कार्यवाहियों की सुनवाई की तारीख नियत करना और उनकी सूचनाएं जारी करना;
- (v) अभिलेखों के किसी प्रकृतित संशोधन का निवेश देना;
- (vi) कार्यवाहियों के पत्रकारों के दस्तावेजों की प्रतियाँ विलाए जाने का आदेश करना;
- (vii) अधिकरण के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए स्वीकृति देना;

(viii) सूचनाओं और अन्य दस्तावेजों को तमिल से सर्वविध सभी मामलों का निपटारा, नई सूचनाओं के जारी किए जाने के लिए या समझ बढ़ाए जाने के लिए आवेदन;

(ix) किसी न्यायालय या अन्य अधिकरण की अभिरक्षा से अभिलेखों की अध्यापना करना;

(x) आवेदन के संबंधित रहने के दौरान मृत पत्रकारों के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व के लिए आवेदन प्राप्त करना;

(xi) वहाँ के सिवाय जहाँ प्रतिनिधित्व से प्राप्त करना या उपस्थित करना अनिवार्य है, प्रतिनिधित्व के लिए आवेदन करना तथा उनका निपटारा करना;

(xii) दस्तावेजों की वापसी के लिए पत्रकारों द्वारा आवेदन प्राप्त करना तथा उनका निपटारा करना।

29. मुद्रा और संप्रतीक—अधिकरण की आधिकारिक मुद्रा और संप्रतीक ऐसा होगा जो सरकार विनियमित रहे।

30. अधिकरण के सदस्यों और कर्मचारियों के लिए पोशाक—अधिकरण के सदस्यों (जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं) और अधिकरण के कर्मचारियों के सदस्यों के लिए पोशाक ऐसी होगी जो अध्यक्ष विनियमित करें।

31. पत्रकारों के लिए पोशाक: प्रत्येक विधि आसानी या यथास्थिति, पीठस्थ अधिकारी अधिकरण के समान अपनी व्यावसायिक पोशाक में यदि कोई हो, हाजिर होगा और यदि ऐसी कोई पोशाक नहीं है, वहाँ—

- (i) यदि वह पुरुष है तो बंद नंगे के कोट या खुले गले के कोट में गहरा कमीज और पैट और टाई अथवा लाउन्ज सूट के साथ हाजिर होगा;
- (ii) यदि वह महिला है तो सफेद नाड़ी या किसी सफेद पोशाक में अथवा अन्य सादे रंग की प्रकृतित पोशाक में हाजिर होगी।

[संख्याए-11019/21/86-ए.टी.क.]

पी. जी. लेले, निदेशक

कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण

बंगलूर

प्रकरण-I

(देखिए नियम 4)

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के अधिन आवेदन मामले का शीर्षक:

अनुक्रमिका

क्रम उन दस्तावेजों का क्रम जिसका अवकाश लिया गया है पृष्ठ संख्या संख्या

आवेदन पत्र

- 1.,
- 2.,
- 3.,
- 4.,
- 5.,
- 5.,
- 6.,

आवेदक के हस्ताक्षर

अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग के लिए

फाइल करने की तारीख
या
डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख
रजिस्ट्रेशन संख्या
हस्ताक्षर
कृते रजिस्ट्रार

क संघ प्रशासनिक अधिकरण, बंगलौर में

के मध्य

का.

का.

आवेदक

और

ग.

ग.

प्रत्यर्थी

आवेदन के दायरे

1. आवेदक की विनिर्दिष्टता :
 - (i) आवेदक का नाम
 - (ii) पिता/पति का नाम
 - (iii) आवेदक की आयु
 - (iv) पद नाम तथा उस कार्यालय के दायरे (नाम तथा स्थान) जिसमें नियुक्त है अथवा सेवा सम्पन्न होने से पहले नियुक्त था।
 - (v) कार्यालय का पता
 - (vi) नोटिसों की तारीख का पता
2. प्रत्यर्थी की विनिर्दिष्टता :
 - (i) प्रत्यर्थी का नाम
 - (ii) पिता/पति का नाम
 - (iii) प्रत्यर्थी की आयु
 - (iv) पदनाम तथा उस कार्यालय के दायरे (नाम तथा स्थान) जिसमें नियुक्त है।
 - (v) कार्यालय का पता
 - (vi) नोटिसों की तारीख का पता
3. उस आवेदन की जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है, विनिर्दिष्ट आवेदन निम्नलिखित आवेदन के विरुद्ध है :
 - (i) आवेदन संख्या
 - (ii) तारीख
 - (iii) द्वारा पारित किया गया
 - (iv) सश्लेष विषय

4. अधिकरण की अधिकारिता :

आवेदक यह घोषणा करता है कि उस आवेदन की जिसके विरुद्ध वह प्रतिलोभ साहता है, विषय-वस्तु अधिकरण की अधिकारिता के अन्तर्गत है।

5. परिसीमाएं :

आवेदक यह और घोषणा करता है कि आवेदन प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 21 में विहित परिसीमा के अन्तर्गत है।

6. मामले के तथ्य :

मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं :—

(यहां क्रमानुसार तथ्यों का एक संक्षेप कथन है, प्रत्येक पैरा में अथवा संभव निकटतम एक पृष्ठक विवरण है, तथा या अथवा अस्तित्व में है।)

7. विशेष किए गए उद्देश्यों के अन्तर्गत

आवेदक यह घोषणा करता है कि उक्त सुसंगत सेवा (तथ्यों प्राप्ति के अन्तर्गत उक्त उद्देश्य तथा उद्देश्यों का उपयोग कर लिया है।

(यहां किए गए आवेदकों के अन्तर्गत और अनुसंधानों का उद्देश्य के अन्तर्गत ऐसे आवेदकों का परिचय क्रमानुसार है।)

8. ऐसे विषय जो पढ़ने किता अन्तर्गत न्यायिक के दायरे अथवा सम्बन्धित नहीं हैं।

आवेदक यह और घोषणा करता है कि उक्त उस मामले के संबंध में जिसके बारे में यह आवेदन पत्र दिया है किसी विधि न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण अथवा अप्रतिष्ठा की किसी अन्य न्यायपीठ के समक्ष पहले कोई आवेदन पत्र, रिट याचिका अथवा वाद न तो पहले दायर किया था तथा न ही ऐसी कोई आवेदन पत्र, रिट याचिका अथवा वाद उनके समक्ष सम्बन्धित है।

यदि आवेदकों ने पहले कोई आवेदन-पत्र, रिट याचिका अथवा वाद दायर किया था तो उस स्थिति (स्टेज) का उल्लेख करते हुए पर यह सम्बन्धित है तथा यदि निर्णय ले लिया गया है तो, अनुसंधानों के अन्तर्गत में निर्णय का गार दिया जाता जाएगा।

9. योग्य गए अनुसंधान

उत्तर पैरा 6 में वर्णित को ध्यान में रखकर आवेदक निम्नलिखित अनुसंधान (यों) के लिए प्रार्थना करता है :

(नीचे माने गए अनुसंधान (यों) को विनिर्दिष्ट करें और अनुसंधान (यों) के आधार और ऐसे विधिक उद्देश्यों (यदि कोई हों) का स्पष्ट करें जिसका अन्तर्गत लिया गया है।)

10. अन्तर्गत आवेदन, यदि उक्त लिए प्रार्थना की गई है :

आवेदन पर अन्तर्गत निम्नलिखित सम्बन्धित रहने तक आवेदक निम्नलिखित अन्तर्गत अधिकारी किये जाने की मांग करता है :—

(यहां कारण देकर उस अन्तर्गत आवेदन को प्रकृति का उल्लेख करें जिसकी प्रार्थना की गई है)

11. अनुसंधानों की सूची :

1.

2.

3.

4.

उत्पादन :

मे (आवेदक का नाम) : पुष्प, पुष्प, पत्नी आयु और कार्यालय/विभाग में के रूप में कार्य कर रहा है/रही है और जो का निवासी है/होती निवासी है यह स्थापित करता है/करती है कि 1 से 15 तक के पैराग्राफों की अस्तित्व में व्यक्तित्व ज्ञान के अनुसार रही है और पैरा 14 में तक की अस्तित्व का कानूनी सजाह के आधार पर सत्य समझा जाता है या कि मैंने किसी भी तात्त्विक तथ्य को नहीं किया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण

बंगलौर

प्राकृप सख्या 2

[परा 4(3) देखें]

गावामी, गरीर

जी/कुभारी/जीमडी

जो विभाग/कार्यक्रम में
के पर पर कार्य कर रहा है/कर रही है तथा जिसका निवास स्थान
है द्वारा कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण
में दाखल किए गए
आवेदन की एगुडारा पावती एकीकरण की जाती है।

हुते रजिस्ट्रार,

कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण

बंगलौर

तारीख

मोहर

परम -3

[विधम 24(3) देखिए]

लिपिक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

पासपोर्ट आकार की सम्पादित
फोटो चिपकाई जाए।

1. बिधि व्यवसायी का नाम जिसको शीर से लिपिक का रजिस्ट्रीकरण
किया जाता है।

2. रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले लिपिक की बिशिष्टियां

- (i) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
- (ii) पिता का नाम
- (iii) आयु और जन्म तिथि
- (iv) जन्म स्थान
- (v) राष्ट्रीयता
- (vi) जोशिक आईना
- (vii) पूर्व नियोजन, यदि कोई है, की बिशिष्टियां।

मैं (ऊपर नामित लिपिक) यह
प्रतिज्ञा करता हूँ कि मुझे संबंधित ऊपर दी गई बिशिष्टियां मालूम हैं।

लिपिक के हस्ताक्षर

3. क्या लिपिक व्यवसायी के पास उसके नियोजन में पहले से ही कोई
रजिस्ट्रीकृत लिपिक है और क्या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला लिपिक
पहले से ही रजिस्ट्रीकृत लिपिक के स्थान पर है या उसके अतिरिक्त है।

4. क्या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला लिपिक किसी अन्य बिधि व्यवसायी
के लिपिक के रूप में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है और यदि हाँ तो ऐसे
बिधि व्यवसायी का नाम।

मैं (बिधि व्यवसायी) प्रमाणित
करता हूँ कि ऊपर दी गई बिशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और
विश्वास के अनुसार सही हैं और यह कि मुझे ऐसे किसी तथ्यों की
जानकारी नहीं है, जिससे लिपिक के रूप में उक्त
(नाम) का रजिस्ट्रीकरण अव्यवस्थित हो जाएगा। मैं, मेरे द्वारा सम्पादित

यह से सम्पादित आवेदक को दाखल आसार की दो फोटो प्रमाण
संलग्न करता हूँ।

बिधि व्यवसायी के हस्ताक्षर

तारीख

स्थान में

रजिस्ट्रार,

कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण,

बंगलौर

G.S.R. 1130(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires.

- (a) "Act" means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);
- (b) "Agent" means a person duly authorised by a party to present an application or reply on its behalf before the Tribunal;
- (c) "applicant" means a person making an application to the Tribunal under section 19;
- (d) "application" means an application made to the Tribunal under section 19;
- (e) "Form" means the Form annexed to these rules;
- (f) "Government" means the Government of Karnataka;
- (g) "legal practitioner" shall have the same meaning as is assigned to it in the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);
- (h) "Registrar" means the Registrar of the Tribunal and includes any officer to whom the powers and functions of the Registrar may be delegated under clause (2) of rule 27;
- (i) "section" means a section of the Act;
- (j) "transferred application" means the suit or other proceeding which has been transferred to the Tribunal under sub-section (1) of section 29;
- (k) "tribunal" means the Karnataka Administrative Tribunal established under sub-section (2) of section 4;

(1) the words and phrases used herein but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Language of the Tribunal.—(1) The language of the Tribunal shall be English :

Provided that the parties to a proceeding before the Tribunal may file documents drawn up in Kannada, if they so desire :

Provided further that a Bench may, in its discretion, permit the use of Kannada in the proceedings. However, the final order shall be in English.

4. Procedure for filing applications.—(1) An application to the Tribunal shall be presented in Form No. 1 by the applicant in person or by an agent or by a duly authorised advocate, to the Registrar or any other officer authorised by the Registrar to receive applications or sent by registered post with acknowledgement due addressed to the Registrar.

(2) The application under sub-rule (1) shall be presented in three complete sets in a paper book form along with one unused file size envelope bearing full address of the respondent. Where the number of respondents is more than one, as many extra copies of the application in paper book form as the number of respondents together with required number of unused file size envelopes bearing the full address of each respondents shall be furnished by the applicant.

(3) The applicant may attach to and present with his application a receipt slip as in Form No. 2 which shall be signed by the Registrar or the officer receiving the applications on behalf of the Registrar in acknowledgement of the receipt of the application.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), the Tribunal may permit—

- (a) more than one person to join together and file a single application if it is satisfied having regard to the cause of action and the nature of relief prayed for that they have the common interest in the service matter; or
- (b) an Association representing the persons desirous of joining in a single application provided, however, that the application shall disclose the names and classification of all the persons on whose behalf it has been filed.

5. Presentation and scrutiny of application.—

(1) The Registrar or the officer authorised by him under rule 4, shall endorse on every application the date on which it is presented or deemed to have been presented under that rule and shall sign the endorsement.

(2) If, on scrutiny, the application is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number.

(3) If the application, on scrutiny, is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Registrar may allow the party to rectify the same in his presence, and if the said defect is not formal in nature, the Registrar may allow the applicant such time to rectify the defect as he may deem fit.

(4) If the applicant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule (3), the Registrar may, by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the application.

(5) An appeal against the order of the Registrar under sub-rule (4) shall be made within 15 days of the making of such order to the Tribunal whose decision thereon shall be final.

6. Place of filing application.—The application shall be filed by the applicant with the Registrar.

7. Application fee.—Every application filed with the Registrar shall be accompanied by a fee of Rs. 50 (rupees fifty only) which shall be paid in court fee stamps affixed on such an application :

Provided that where the Tribunal permits a single application to be filed, either by more than one person or by an Association, the fee payable shall be Rs. 50 (rupees fifty) only.

8. Contents of application.—(1) Every application filed under rule 4 shall set forth concisely under distinct heads, the grounds for such application. Such grounds shall be numbered consecutively and typed on a thick paper of good quality in double space on one side.

(2) It shall not be necessary to present a separate application to seek an interim order or direction if the application contains a prayer seeking an interim order or direction pending final disposal of the application.

(3) An applicant may subsequent to the filing of application under section 19 of the Act, apply for an interim order or direction. Such an application shall, as far as possible, be in the same form as is prescribed for an application under section 19 and shall be accompanied by a fee of Rs. 2 (rupees two only) which shall be payable in court fee stamps affixed on such an application.

9. Documents to accompany the application.—

(1) Every application shall be accompanied by a paper book containing—

- (i) an attested true copy of the order against which the application has been filed;
- (ii) copies of the documents relied upon by the applicant and referred to in the application; and
- (iii) an index of documents.

(2) The documents referred to in sub-rule (1) may be attested by a Notary Public or by a Gazetted Officer and each document shall be marked serially as Annexure A-1; A-2; A-3 and so on.

(3) Where the application is filed by an agent, documents authorising him to act as such agent shall also be appended to the application:

Provided that where an application is filed by a legal practitioner it shall be accompanied by a duly executed 'Vakalatnama'.

10. Plural remedies.—An application shall be based upon a single cause of action and may seek one or more reliefs provided they are consequential to one another.

11. Service of notice of application on the respondent.—

(1) A copy of the application in the paper book shall ordinarily be served on each of the respondents by the Registrar in one of the following modes :—

- (i) hand delivery (dasti) through the applicant or through a process server; or
- (ii) through registered post with acknowledgement due; or
- (iii) through the concerned Head of the Department by any of above modes.

(2) Where the notice issued by the Tribunal is served by the applicant himself by hand delivery (Dasti), he shall file with the Registrar the acknowledgement together with an affidavit of service and such service shall be deemed to be sufficient service.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Registrar may, taking into account the number of respondents and their places of residence or work and other circumstances, direct that notice of the application shall be served upon the respondents in any other manner, including any manner of substituted service, as it appears to the Registrar just and convenient.

(4) Standing Counsels appointed by Government shall receive notices on behalf of the Government or its Departments subject to such directions as the Tribunal may deem fit having regard to the nature and urgency of the matter.

(5) Every notice issued by the Tribunal, unless otherwise directed, shall be accompanied by a copy of the application, along with the paper book.

(6) Every applicant shall pay a fee for the service or execution of processes, in respect of an application where the number of respondents exceeds five, as under—

- (i) a sum of Rs. 5 (rupees five only) for each respondent in excess of five respondents; or
- (ii) where the service is in such manner as the Registrar may direct under sub-rule (3), a sum not exceeding the actual charges incurred in effecting the service as may be determined by the Registrar.

(7) The fee for the service or execution of processes under sub-rule (3) or sub-rule (6) shall be remitted by the applicant in the form of court fee stamps.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), (3) and (4), if the Tribunal is satisfied that it is not reasonably practicable to serve notice of application upon all the respondents, it may for reasons to be recorded in writing direct that the application shall be heard notwithstanding that some of the respondents have not been served with notice of the application, provided that no application shall be heard unless,—

- (i) notice of the application has been served on the Government or the Central Government if that Government is a respondent;

(ii) notice of the application has been served on the authority which passed the order against which the application has been filed; and

(iii) the Tribunal is satisfied that the interests of the respondents on whom notice of the application has not been served are adequately and sufficiently represented by the respondents on whom notice of the application has been served.

12. Filing of reply and other documents by the respondents.—

(1) Each respondent intending to contest the application shall file three complete sets containing the reply to the application alongwith the documents relied upon by him, in a paper book form, with the Registrar within one month of the date of service of the notice of the application on him.

(2) In the reply filed under sub-rule (1), the respondent shall specifically admit, deny or explain the facts stated by the applicant in his application and may also state such additional facts as may be found necessary for the just decision of the case. It shall be signed and verified as a written statement by the respondent or any other person duly authorised by him in writing in the same manner as provided for in Order VI, rule 15 of the Code of Civil Procedure.

(3) The documents referred to in sub-rule (2) shall also be filed along with the reply and marked as R1, R2, R3 and so on.

(4) The respondent shall also serve a copy of the reply along with copies of documents as mentioned in sub-rule (1) on the applicant or his legal practitioner, if any, and file proof of such service with the Registrar.

(5) The Registrar may, on application by the respondent, allow filing of the reply after the expiry of the period of one month.

13. Date and place of hearing to be notified. The Registrar shall notify to the parties or their counsels, if any, the date and the place of hearing of the application.

14. Sitting of the Tribunal.—The Tribunal shall ordinarily hold its sittings at Bangalore :

Provided that, if at any time, the Chairman of the Tribunal is satisfied that circumstances exist which render it necessary to have sittings of the Tribunal at any place other than Bangalore, the Chairman may direct to hold the sittings at any such appropriate place.

15. Decision on application.—(1) The Tribunal shall draw up a calendar for the hearing of transferred applications and as far as possible hear and decide the cases according to the calendar.

(2) Every application shall be heard and decided, as far as possible, within six months of the date of its presentation.

(3) For purposes of sub-rules (1) and (2), the Tribunal shall have the power to decline an adjournment and to limit the time for oral arguments.

16. Action on application for applicant's default.—

(1) Where on the date fixed for hearing of the application or on any other date to which such hearing may be adjourned, the applicant does not appear when the application is called on for hearing, the Tribunal may, in its discretion, either dismiss the application for default or hear and decide it on merit.

(2) Where an application has been dismissed for default and the applicant appears afterwards and satisfies the Tribunal that there was sufficient cause for his non-appearance when the application was called on for hearing, the Tribunal may make an order setting aside the order dismissing the application and restore the same.

17. Hearing of application ex-parte.—(1) where on the date fixed for hearing the application or on any other date to which such hearing may be adjourned, the applicant appears and the respondent does not appear when the application is called on for hearing, the Tribunal may, in its discretion, adjourn or hear and decide the application ex-parte.

(2) Where an application has been heard ex-parte against a respondent or respondents, such respondent or respondents may apply to the Tribunal for an order to set aside; and if such respondent or respondents satisfy the Tribunal that the notice was not duly served, or that he or they were prevented by any sufficient cause from appearing when the application was called on for hearing, the Tribunal may make an order setting aside the ex-parte hearing as against him or them upon such terms as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the application :

Provided that where the ex-parte hearing of the application is of such nature that it cannot be set aside as against one respondent only, it may be set aside as against all or any of the other respondents also :

Provided further that no Tribunal shall set aside ex-parte hearing of an application merely on the ground that there has been an irregularity in the service of notice, if it is satisfied that the respondents had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the applicant's claim.

18. Adjournment of application.—The Tribunal may on such terms as it deems fit and at any stage of the proceedings adjourn the hearing of the application.

19. Order to be signed and dated.—Every order of the Tribunal shall be in writing and shall be signed and dated by the members constituting the Bench concerned.

20. Publication of orders.—Such of the orders of the Tribunal as are deemed fit for publication in any authoritative report or the press may be released for such publication on such terms and conditions as the Tribunal may lay down.

21. Communication of orders to parties.—

(1) Every order passed on an application shall be communicated to the applicant and to the respondent either in person or by registered post free of cost.

(2) Certified copies of the order of proceedings may be obtained by the parties on application to the Registrar on payment of such fees and on such terms and conditions as may be prescribed by the Chairman by any general or special order.

22. No fee for inspection of records.—No fee shall be charged for inspecting the records of a pending application by a party thereto.

23. Orders and directions in certain cases.—

The Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to, or in relation to, its orders or to prevent abuse of its process or to secure the ends of justice.

24. Registration of legal practitioner's clerks.—

(1) A clerk employed by a legal practitioner and permitted as such to have access to the records and to obtain copies of the orders of the Tribunal in which the legal practitioner ordinarily practises shall be known as a "registered clerk".

(2) A legal practitioner desirous of registering his clerk shall make an application to the registrar in Form 3 with three passport size photographs of the clerk—One pasted on the application form and the other two loosely attached to it.

(3) A legal practitioner shall have at any one time not more than two registered clerks unless the Registrar by general or special order otherwise permits.

(4) A register of all the registered clerks shall be maintained in the Office of the Registrar and after registration of the clerk, the Registrar shall direct the issue of an identity card to him which shall be non-transferable and shall be produced by the holder upon request by an officer or any other employee of the Tribunal.

(5) The identity card mentioned in sub-rule (4) shall be issued under the signature of the Deputy Registrar of the Tribunal.

(6) Whenever a legal practitioner ceases to employ a registered clerk, he shall notify the fact at once to the Registrar by means of a letter enclosing therewith the identity card issued to his clerk and on receipt of such letter the name of the said registered clerk shall be struck off the register.

(7) The registration of a clerk shall be valid for a period of one year and shall be subject to annual renewal.

25. Working hours and working days of the Tribunal :

(1) The Tribunal shall observe the same working hours as the offices of the Government. The Tribunal shall remain closed on Sundays and on such holidays as may be declared by the Government for its offices.

(2) The Chairman shall notify and determine the days during which the vacation of thirty days in one or more spells shall be observed by the Tribunal.

26. Sitting hours of the Tribunal.—The sitting hours of the Tribunal (including the vacation Bench)

shall ordinarily be, from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. and 3.00 P.M. to 5.00 P.M. subject to any order made by the Chairman.

27. Powers and functions of the Registrar.—

(1) The Registrar shall have the custody of the records of the Tribunal and shall exercise such other functions as may be assigned to him under these rules or by the Chairman.

(2) The Registrar may, with the approval of the Chairman, delegate to Deputy Registrar any function required by these rules to be exercised by the Registrar.

(3) In the absence of the Registrar, the Deputy Registrar or any other officer of the Tribunal authorised in writing by the Chairman in this behalf, may perform or exercise all or any of the functions and powers of the Registrar.

(4) The Registrar shall keep in his custody official seal of the Tribunal.

(5) The Registrar shall, subject to any general or special direction by the Chairman, affix the official seal of the Tribunal on any order, notice or other process.

(6) The Registrar shall have the power to authorise in writing the affixing of the seal of the Tribunal on a certified copy of any order of the Tribunal.

28. Additional powers and duties of Registrar.—In addition to the powers conferred elsewhere in these rules, the Registrar shall have the following powers and duties subject to any general or special order of the Chairman or the Vice-Chairman of the Bench concerned, namely :—

- (i) to receive all applications and other documents including transferred applications;
- (ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the applications before they are registered;
- (iii) to require any application presented to the Tribunal to be amended in accordance with the Act and the rules;
- (iv) subject to the directions of the Tribunal to fix dates of hearing of the applications or other proceedings and issue notices thereof;
- (v) to direct any formal amendment of records;
- (vi) to order grant of copies of documents to parties of the proceedings;
- (vii) to grant leave to inspect the records of the Tribunal;
- (viii) to dispose of all matters relating to the service of notices or other processes, applications for the issue of fresh notices or for extending the time therefor;
- (ix) to requisition records from the custody of any court or other authority;

(x) to receive applications for the substitution of legal representatives of the deceased parties, during the pendency of the application;

(xi) to receive and dispose of application for substitution, except where the substitution would involve setting aside an order or abatement; and

(xii) to receive and dispose of application by parties for return of documents.

29. Seal and emblem.—The official seal and emblem of the Tribunal shall be such as the Government may specify.

30. Dress for the Members and staff of the Tribunal.—The dress for the Members of the Tribunal (including Chairman and Vice-Chairman and members of the staff of the Tribunal shall be such as the Chairman may specify.

31. Dress for the parties.—A legal practitioner or, as the case may be, a presenting officer shall appear before the Tribunal in his professional dress if any, and if there is no such dress,—

(i) if a male, in a close collared or in an open collared coat with white shirt, trousers and a tie or in a lounge suit;

(ii) if a female, in a saree or in any other dress in white or any other customary dress of sober colour.

[No. A-11019/21/86-AT]

P. G. LELE, Director (AT)

KARNATAKA ADMINISTRATIVE TRIBUNAL BANGALORE

FORM NO. 1

(See Rule 4)

APPLICATION UNDER SECTION 19 OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ACT, 1985.

Title of the Case :

INDEX

S. No.	Description of documents relied upon	Page No.
1.	Application	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Signature of the applicant

For use in Tribunal's Office

Date of filing
or
Date of Receipt by post
Registration No.

Signature
For Registrar

**IN THE KARNATAKA ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
BANGALORE**

BETWEEN

B APPLICANT

AND

D RESPONDENT

DETAILS OF APPLICATION :

1. Particulars of the applicant :

- (i) Name of the applicant.
- (ii) Name of Father/Husband
- (iii) Age of the applicant
- (iv) Designation and particulars of office (Name and station) in which employed/or was last employed before ceasing to be in service.
- (v) Office address
- (vi) Address for service of notices.

2. Particulars of the respondent :

- (i) Name of the respondent
- (ii) Name of Father/Husband
- (iii) Age of the respondent
- (iv) Designation and particulars of office (name and station) in which employed.
- (v) Office address
- (vi) Address for services of notices.

3. Particulars of the order against which application is made.

The application is against the following order :—

(i) Order No.

With reference to Annexure

- (ii) Date
- (iii) Passed by
- (iv) Subject, in brief.

4. Jurisdiction of the Tribunal :

The applicant declares that the subject matter of the order against which he wants redressal is within the jurisdiction of the Tribunal.

5. Limitation :

The applicant further declares that the application is within the limitation prescribed in section 21 of the Administrative Tribunals Act, 1985.

6. Facts of the case :

The facts of the case are given below :—

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise).

7. Details of the remedies exhausted :

The applicant declares that he has availed of all the remedies available to him under the relevant service rules, etc.

(Give here chronologically the details of representations made and the outcome of such representations with reference to the Annexure numbers).

8. Matters not previously filed or pending with any other court.

The applicant further declares that he had not previously filed any applications, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this application has been made

before any court of law or any other authority or any other Bench of the Tribunal and nor any such application writ petition or suit is pending before any of them.

In case the applicants had previously filed any application, writ petition or suit, the stage at which it is pending and if decided, the gist of the decision should be given with reference to the Annexures.

9. Relief(s) sought

In view of the facts mentioned in para 6 above, the applicant prays for the following relief (s) :—

[Specify below the relief(s) sought explaining the ground for relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon].

10. Interim order, if any prayed for :

Pending final decision on the application, the applicant seeks issue of the following interim order : (Give here the nature of the interim order prayed for with reasons).

11. List of enclosures :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

VERIFICATION

I,.....(Name of the applicant), S/o, D/o, W/o....., Ageworking as.....in the office of/Department of.....and residing at.....do hereby verify that the contents of paras 1 to 15 are true to my personal knowledge and para 14 to.....believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any material fact.

Signature of the applicant

Date :

Place :

To

The Registrar,
Karnataka Administrative Tribunal,
Bangalore.

FORM NO. 2

[See Rule 4(3)]

RECEIPT SLIP

Receipt of the Application file in the Karnataka Administrative Tribunal.....by Shri/Kum./Smt.working as.....in the Department/Office of.....residing at.....is hereby acknowledged.

For Registrar,
Karnataka Administrative Tribunal
BANGALORE

Date :

SEAL :

FORM NO. 3

[See Rule 24(2)]

APPLICATION FOR THE REGISTRATION OF A
CLERK

Attested passport size Photograph to be pasted

1. Name of legal practitioner on whose behalf the clerk is to be registered.
2. Particulars of the clerk to be registered
 - (i) Full Name :
(in capital)
 - (ii) Father's Name :
 - (iii) Age and Date of Birth :
 - (iv) Place of Birth :
 - (v) Nationality :
 - (vi) Educational Qualifications
 - (vii) Particulars of previous employment, if any.

I,..... (Clerk
above named) do hereby affirm that the particulars relating
to me given above are true.

Signature of Clerk

3. Whether the legal practitioner has a clerk already registered in his employ and whether the clerk sought to be registered is in lieu of or in addition to the clerk already registered.
4. Whether the clerk sought to be registered is already registered as a clerk of any other legal practitioner and is so, the name of such practitioner.

I,..... (legal
practitioner) certify that the particulars given above are true
to the best of my information and belief and that I am not
aware of any fact which would render unsuitable the registra-
tion of the said.....
(name) as a clerk. Further, I enclose 2 Passport size Photo-
graphs of the applicant duly attested by me.

Signature of legal practitioner

Date :
To

The Registrar,
Karnataka Administrative Tribunal
Bangalore.

